आवश्यकता है

दैनिक गुरु एक्सप्रेस

गुरु एक्सप्रेस की प्रिंटिंग यूनिट पर रात्रि के समय 11 से 3 बजे तक काम करने वाले युवक (हेल्पर)की आवश्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार

संपर्क

संपर्क समय- शाम 4 से 6 बजे तक

कार्यालय दैनिक गुरु एक्सप्रेस

9425105928. 8319964648

डाक पंजीयन क्र. L/ RNP/म.प्र./ मन्दसौर/122/ 2024- 26

ई-पेपर www.guruexpress.live

बात आपकी, शब्द हमारे

गुरु एक्सप्रेस

सुबह का अखबार

संपादक – आशुतोष नवाल

वर्ष 18 | अंक 127 | पृष्ठ 4 | मन्दसौर | शनिवार 17 फरवरी 2024 | मूल्य 2 रुपया

फिर शुरू हुई मरीजों की तस्करी..!

लोकल निजी अस्पताल ले जाने के 1500 रुपए...

एंबुलेंस संचालक और दलाल मंडरा रहे अस्पताल में, नौ नंबर से लेकर वार्डो तक तगड़ी सेटिंग

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। बड़े अस्पताल में एंबुलेंस माफियाओं की सक्रियता और गुंडागर्दी के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया था। यातायात पुलिस ने करीब डेढ़ दर्जन एंबुलेंस जब्त की थी। अब यातायात थाने में सिर्फ तीन एंबुलेंस बची है। बाकी सभी औपचारिक खानापूर्ती कर छुड़वाकर ले गए। हालांकि स्थिति फिर पहले जैसी हो गई है। बड़े अस्पताल में एंबुलेंस संचालकों और दलालों को देखा जा सकता है। जबकि, अस्पताल में पोस्टर फाड़ने की घटना के बाद कलेक्टर-एसपी ने सख्त निर्देश दिए थे कि निजी एंबुलेंस संचालक या ड्रायवर अस्पताल में नजर नहीं आएंगे। लेकिन, पुलिस चौकी के आसपास ही इन्हें देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आकस्मिक चिकित्सा कक्ष नौ नंबर और वार्डो का कुछ स्टॉफ भी एंबुलेंस माफियाओं के साथ गिरोह बनाकर काम कर रहा है। मरीजों की मानो तस्करी हो रही है। खुलेआम कमीशन का खेल खेला जा रहा है। यह भी बात सामने आई है कि उदयपुर के कुछ निजी अस्पतालों ने बड़े अस्पताल से रैफर मरीजों को अपने यहां लाने का जाल

खुले आम कमीशन पर काम करते एंबुलेंस संचालक

बिछा रखा है। जहां से मरीजो से खेंची गई राशि में से 20 प्रतिशत एम्बूलेंस संचालको को दी जाती है। मंदसौर में चल रही कई एंबुलेंस उदयपुर के निजी अस्पताल संचालक या उसमें पदस्थ कर्मचारियों द्वारा फाइनेंस करवाई गई हैं। किश्त मरीजों के बिल से मिलने वाले कमीशन से कटती है, जो बिल राशि का 20 प्रतिशत है।

मरीज के आते ही पता चल जाता एंबुलेंस संचालकों को...

एक साल पहले सख्ती करते हुए एसपी-कलेक्टर ने खुद एंबुलेंस संचालकों और दलालों की अस्पताल में इंट्री पर सख्ती से रोक लगा दी थी। साथ ही परिसर ही नहीं, बल्कि अस्पताल के आसपास एंबुलेंस नहीं खडी रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। इसी के तहत 17 एंबुलेंस भी यातायात पुलिस ने जब्त की। एक बार फिर निजी एंबुलेंस बड़े अस्पताल और आसपास मंडराने लगी है। एंबुलेंस संचालकों को और दलालों को बड़े अस्पताल में देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रैफर जैसे मरीज के आते ही एंबुलेंस संचालकों को पता चल जाता है। इसके अलावा वार्डो में भर्ती मरीज के रेफर जैसी हालत होते ही जानकारी एंबुलेंस संचालकों तक पहुंच जाती है। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी इस गिरोह में शामिल है।

साल में 3600 मरीज पर खर्च होते हैं 40 करोड़...

बड़े अस्पताल से जाने वाले मरीजों से उदयपुर के निजी अस्पतालों को 40 करोड़ रुपए सालाना का व्यापार मिलता है। अस्पताल से सर्जिकल, आर्थोपेडिक व इमरजेंसी वार्ड से 10 मरीज रोज रैफर होते हैं। यानी हर तीसरे घंटे गंभीर मरीज। एंबुलेंस संचालक उन्हें उदयपुर के निजी अस्पताल ही ले जाते हैं। ऐसे में सालभर में 3600 मरीज उदयपुर पहुंचते हैं। औसतन 1 लाख का बिल हो तो भी 36 करोड रुपए का व्यापार उदयपुर के निजी अस्पताल सिर्फ मंदसौर के मरीजों से ही करते हैं। इसके अलावा अन्य कई मरीज ऐसे होते हैं, जिनके तीन से चार लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। कई मरीज तो इसके बाद भी बच नहीं पाते।

आठ माह पहले एसडीएम ने दिए थे आदेश...

आठ माह पहले एसडीएम ने निजी एंबुलेंस को लेकर आदेश जारी किए थे। जिसमें कहा गया था कि अब निजी एम्बुलेंस को स्टेडियम मार्किट ग्राउंड में नियत स्थान दिए गया है। सभी निजी एम्बुलेंस पार्किंग यहीं पर होगी। अन्य किसी स्थान पर प्रतिबंध रहेगा। सभी निजी एम्बुलेंस संचालक का बड़े अस्पताल परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जब तक किसी मरीज को लेकर अस्पताल में आना या जाना हो। सभी एम्बुलेंस वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, चालक ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक एम्बुलेंस संचालक को थाना प्रभारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, परिवहन विभाग से वाहन का प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एम्बुलेंस के आवश्यक समस्त चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध होने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त कर सब-डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट मंदसौर को प्रस्तुत करना होगा। इसकी जांच के बाद ही अनुमति जारी की जा सकेगी। सभी एंबुलेंस वाहन में जीपीएस सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई मरीज बड़े अस्पताल में आता है तो जहां उसे आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में डॉक्टर देख रहे होते है, उसी समय एम्बूलेंस संचालक और दलाल आ जाते है। वे डाक्टर के सामने ही मरीज के परिजनो से कहने लगते है कि यहां इलाज नहीं हो पाएगा। फिर मरीज या परिजनो की सहमति के बगैर ही एम्बूलेंस में डालकर शहर के निजी अस्पताल में ले जाते है, जिसके 1500 रूपए मिलते है। जबकि, उस अस्पताल में यदि उपचार होता है तो फिर जितने का बिल बनता है, उसके अनुसार 10-20 प्रतिशत राशि मिलती है। पिछले दिनो भी एक ऐसे ही मामले में गुराड़िया बायपास पर हुई दुर्घटना में घायल बुजुर्ग को जबरन ही बड़े अस्पताल से निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां दो दिन में 80 हजार रूपए का बिल बना और उसे कह दिया गया कि उदयपुर या अहमदाबाद ले जाओ। बेचारे गरीब परिवार ने जैसे-तैसे बुजुर्ग का उदयपुर ले जाकर उपचार कराया।

गांधीसागर अभ्यारण्य: चीतों को लेकर उत्साह, अतिक्रमण को लेकर उदासीनता

मंदसौर/भानपुरा, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। गांधी सागर में फेस्टिवल सहित अन्य इवेंट आयोजित करने के साथ ही चीते बसाने की योजना भी लगभग पूरी होने वाली है। इसको लेकर खासा उत्साह भी है। लेकिन, यहां अतिक्रमण को कहीं न कहीं नजर अंदाज किया जा रहा है। अतिक्रमण पर खुद सर्वे रिपोर्ट ने मुहर लगाई थी। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों को फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। जबकि, तत्कालीन कलेक्टर गौतमसिंह ने इस संबंध में शासन को अवगत कराने की बात भी कहीं थी।

बता दें कि कुछ समय पहले गांधी सागर बांध की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे। एक साल पहले जिले में स्थित गांधीसागर बांध का प्रशासन ने सर्वे करवा। जिसमें गांधीसागर बांध तो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन सर्वे में सामने आया है कि बांध क्षेत्र में रिक्त पड़ी सरकारी जमीन पर बड़े पैमानें पर अतिक्रमण फैल चुका है जो दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। सिंचाई विभाग से लेकर वन विभाग की जमीन इस क्षेत्र में है ओर दोनों विभागों की जमीन पर ही अतिक्रमण सामने आया है। प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाने की बात कही गई थी। बाद में अधिकारियों के स्थानांतरण और चुनावी माहौल में अतिक्रमण का मुद्दा जिम्मेदार भूल गए।

चुनौतीपूर्ण यह है कि यहां अतिक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। लगातार अतिक्रमण बढता जा रहा है। गांधीसागर बांध के बैक वॉटर क्षेत्र में खुली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण है तो वन विभाग की जमीनों पर भी अतिक्रमण सामने आया था। अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या भी अत्यधिक है। यहां कई लोग आवासीय रुप में रह रहे है। लेकिन विभागों के नाम जमीन पर आवासीय पट्टे भी नहीं मिल सकते और प्रशासन इन्हें यूं हटा भी नहीं सकता है। जब तक अन्य जगहों पर इनके रहने की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में पूरा मामला शासन के संज्ञान में लाने की जरुरत थी। वहां से मिले निर्देशों पर अब गांधीसागर मामले में प्रशासन अपने कदम आगे बढा सकता है। सर्वे की रिपोर्ट भी विस्तृत तैयार हुई। इसमें गांधीसागर और इससे जुडे क्षेत्र में मकानों से लेकर हर एक चीज की जानकारी को शामिल किया गया है।

एक वर्ष पहले सर्वे में आया था अतिक्रमण

कई काम चल रहे है गांधी सागर से...

एशिया की पहली मानव निर्मित गांधीसागर झील कई मायनों में अहम है। यहां से सिंचाई की कई बडी योजनाओं से किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है। अब गांधीसागर के पानी से रतलाम, मंदसौर व नीमच जिले के गांवों में घरों तक पेयजल पहुंचाने पर काम चल रहा है। सिंचाई विभाग के लिए गांधीसागर जितना अहम है उतना ही वन विभाग के नजरीए से भी अहम है। गांधीसागर अभयारण्य भी अब विकसित हो रहा है। यहां चीतो को लाने की तैयारी है तो कई पशु-पक्षियों से लेकर दुर्लभ जीव-जतुंओं ने गांधीसागर को अपना बसेरा बनाया है तो गांधीसागर में विद्युत उत्पादन भी हो रहा है। इसके अलावा भी कई मायनों में यह अहम है। ऐसे में इस गंभीर मुद्दें पर कई दिनों तक चले सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार हुई। इसमें सबसे बडी समस्या बढता अतिक्रमण आई है। अब इस पर शासन के निर्देश का प्रशासन को इंतजार है।

इनका कहना...

वन क्षेत्र की जमीन पर कोई अतिक्रमण जैसी बात सामने नहीं आई है। अगर सर्वे में इस तरह की कोई स्थिति सामने आई थी तो उसको दिखवाकर आगे की कारवाई की जाएगी।

संजय रायखेरे
डीएफओ, मंदसौर

नीमच गोलीकांड: दो बदमाशों की तलाश जारी

नीमच, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। समाजसेवी और व्यवसाई अशोक अरोरा हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि, 2 फरार बदमाशो की तलाश जारी है।

पुलिस ने शुक्रवार को फरार चल रहे आरोपी आशिक पटेल को इंदौर जिले के गौतमपुरा से जबकि शाहिद हुसैन को उदयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। जिन्हें मेडिकल करवाने के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से आरोपियों को पुलिस रिमांड के लिए सौंपा गया है। गोली कांड के मामले में पुलिस ने अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें मुख्य साजिशकर्ता बाबू सिंधी उर्फ जयकुमार सबनानी, अशोक अरोरा का छोटा भाई राकेश अरोरा, मोबाइल उपलब्ध करवाने वाला नसीर अहमद, शूटर अकरम शाह, आशिक पटेल, शाहिद हुसैन, रैकी करने वाले आरोपी कल्लू और गुलफाम को गिरफ्तार किया है। जबकि एक शूटर बाबू फकीर मौके पर ही मारा जा चुका है।

बाबा साहेब की प्रतिमा से कपड़ा हटाने वाले गिरफ्तार

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। पिपलिया मंडी के ग्राम मुंदेड़ी में नवनिर्मित बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा से अनावरण से पहले ही किसी ने कपड़ा हटा दिया। पुलिस ने जांच कर दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है।

फरियादी विष्णु रसोतिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसमें बताया कि ग्राम मुन्दड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर की नवनिर्मित प्रतिमा जिसका अनावरण होना बाकी है। जिसके कारण इस पर कपड़ा लगाया था। उस कपड़े के आवरण को शराब के नशे में ग्राम मुन्दडी के राकेश और सुभाष मेघवाल द्वारा हटाया गया। जिससे मेरी व गांव के लोगो की भावनाएं आहत हुई है। उक्त आवेदन पत्र पर से आरोपी सुभाष मेघवाल पिता स्व. केशूराम मेघवाल एवं राकेश पिता रमेशचन्द मेघवाल के विरूद्ध धारा 502(2) भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

बता दें कि पुलिस द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां पर सीसीटीवी केमरों को लगवाकर उसका लाईव फीड अपने मोबाईल पर देखे जाने की सुविधा संचालित की गई थी। ताकि कोई असामाजिक तत्व, वर्ग विशेष एवं जन समुदाय की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से प्रतिमा के साथ छेड़खानी ना करे। उक्त स्थल पर सीसीटीवी में घटना को देखा गया। जिसमें 15 फरवरी 2024 की रात्रि 10.30 से 11.00 बजे के मध्य आरोपी सुभाष मेघवाल और राकेश मेघवाल प्रतिमा के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाने के बाद मूर्ति पर चढ़कर कपड़ा निकालकर फोटो निकालते हुए दिख रहे है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पिपलिया मण्डी पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से उनको न्यायिक निरोध में जिला जैल मंदसौर भेजा गया।

पद्रह किलो छिलके के साथ एक गिरफ्तार

भानपुरा, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। पुलिस ने 15 किलो डोडाचूरा के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। उसके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

भैसोदामंडी चौकी पुलिस ने बताया कि मुखबीर सूचना मिलने पर माल गोदाम के पास भैसोदामंडी में दबिश दी गई। इस दौरान मुकेश पिता शंभुलाल मालवीय निवासी पिपलिया पीथा जिला रतलाम की तलाशी ली गई। जिसके पास डोडाचूरा मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है।

एक्टिवा सवार को टक्कर मारने वाली कार चालक महिला को छह माह की सजा

नीमच, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा तेजगती से लापरवाहीपूर्वक कार चलाते हुवे टक्कर मारकर एक्टीवा चालक को गंभीर चोट पहुंचाने वाली महिला आरोपी संगीता पति प्रहलाद पाटीदार आयु 42 वर्ष निवासी बंगला नंबर 58 जिला-नीमच को छह माह की सजा सुनाई है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा यह जानकारी दी गई। उन्होनें बताया कि घटना 1 अक्टूबर 2018 सुबह कमल चौक नीमच की हैं। घटना दिनांक को फरियादिया चांदना अजमेरा उसके पति सुशील अजमेरा के साथ एक्टीवा वाहन से पुस्तक बाजार से सब्जी मंडी की तरफ जा रहे थे कि पीछे से आरोपिया ने उसकी वेगनआर कार को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुवे एक्टीवा को टक्कर मार दी, जिस कारण दोनो गिर गये व दोनो को चोटे आई तथा सुशील की पसलीयों में फ्रैक्चर हो गया था। फरियादीया द्वारा कार चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई।

विवेचना के दौरान कार चालक का पता लगाकर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान दोनो आहतगण, चश्मदीद साक्षीगण तथा शेष सभी महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान कराकर आरोपिया के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपिया को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा की गई।

तमाम अवरोधों के बावजूद संघर्ष और त्याग ने पहुंचा दिया राज्यसभा

मंदसौर/उज्जैन, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। राजतंत्र हो या राजनीति इस राह में फतह पाने के लिए भाग्य का साथ होना अहम रहता है। सीधे रास्ते चले तब भी प्रतिस्पर्धी निपटाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। फिर दल चाहे कोई सा भी हो। मतलब साफ है कि राजनीतिक जगत में काम करते रहने के बाद भी इनाम तभी मिल पाता है, जब भाग्य साथ देता है। तब इनाम पाने वाला कार्यकर्ता नेता हो जाता है और इसके निशाने पर वे कार्यकर्ता आ जाते हैं, जिन्होंने नवनिर्वाचित स्थापित हो चुके नेता की राह में बीते समय कांटे बिछाए थे। राजनीतिक दुनिया में यह बात बहुत ही आम है। इसलिए इस स्पर्धा में जितने भी कार्यकर्ता पात्र होते हैं। उनमें जिसने अपने साथी कार्यकर्ता की राह में कांटे बिछाए होते हैं, उसे खुद सच मालूम होता है और दूसरा वह जिसको मंजिल पाने के लिए इन कांटों पर चलना पड़ा था। राजनीतिक दुनिया में यह बात बहुत ही आम है। इसलिए इस स्पर्धा में जितने भी कार्यकर्ता पात्र होते हैं, उनमें जिसने अपने साथी कार्यकर्ता की राह में कांटे बिछाए होते हैं उसे खुद सच मालूम होता है।

राजनीतिक दुनिया में ऐसी प्रतिस्पर्धा उन क्षेत्रों, जिलों में बहुत ही कड़ी और आक्रामक होती है। जहां समाज सेवा से मान सम्मान के अलावा प्रभाव, प्रशंसा और धनबल की बाढ़ स्वतः गृह प्रवेश कर जाती है। और यही कारण रहता है कि जो भी पहले योग्य पद पर पहुंचता है, वह दूसरों के रास्ते पर यहां तक की अपने करीबी साथी कार्यकर्ताओं के रास्ते पर भी कांटे बिछाते आए हैं। कुछ ऐसे ही रास्ते, ऐसे ही परिस्थितियों में 25 सालों से चलते हुए बंशीलाल गुर्जर कार्यकर्ता बने रहे थे। जबकि, नेता बनने की संभावित योग्यताओं में युवा होने तक पारंगत हो चुके थे। इसलिए भाग्य की प्रबलता पर बल दिया गया है।

गुर्जर की राजनीतिक यात्रा यही परिलक्षित कर रही है। बांनगी देखिए 1978 में 18 साल की उम्र में पंच बने और 5 साल बाद सरपंच से जनपद सदस्य, इसी साल मंडल महामंत्री फिर बने किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, मंडी संचालक से अध्यक्ष बनने तक का सफर भी पूरा कर अगले दशक में जिला अध्यक्ष बने। मंडी संचालक से मंडी अध्यक्ष का सफर अगले दशक में गुजारा, इसी के साथ 2006 से 11 तक प्रदेश मंडी बोर्ड के सदस्य भी रहते हुए मंदसौर जिले की सभी मंडियों का विकास आज सतह पर नजर आ रहा है। फिर दो बार प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा और प्रदेश महामंत्री भाजपा रहने के बाद भी विधानसभा, लोकसभा प्रत्याशी नहीं बन पाए थे। बावजूद इसके कभी बीजेपी संगठन के किसी भी निर्देश की उपेक्षा नहीं की थी। उल्टे ज्यादा सक्रियता से भाजपा के लिए काम करते रहे थे। ऐसा नहीं था की काबिलियत की कमी थी, 18 साल की उम्र से चुनाव लडने का अनुभव 40 साल की उम्र तक परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता में बदल चुका था। इतने सालों के साथी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में मजबूत कार्यकर्ता पदाधिकारी दावेदार होने का पुख्ता वातावरण रहने के बाद भी प्रतिस्पर्धियों और भाग्य ने कभी समूह बनाकर तो कभी क्षेत्रीय विसंगति बता कर रोका गया।

चन्द्रमोहन भगत

बंशीलाल गुर्जर को अपनी पार्टी के लिए जनता के बीच मेहनत और समर्पण से काम करते हुए यथायोग्य पद पाने के लिए 40 सालों का समय गुजारना पड़ा। देश भर में किसान नेता की ख्याति पा चुके गुर्जर के पास अब पार्टी का, अपने जनमानस का, क्षेत्र का विकास करने के लिए पहले से ज्यादा ताकत है। अभी तक पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, किसान मोर्चा प्रदेश संगठन में जहां भी जिस जिम्मेदारी पर रहे अपने कामों के निशान छोड़ते आए हैं। उम्मीद की निगाहें अब राज्यसभा के कार्यकाल पर रहेगी। दावा किया जा सकता है कि देखने सुनने वाले निराश नहीं होंगे। क्योंकि, कटीले अवरोधों की चुभन को रास्ते से हटाने का अनुभव धैर्य और प्रगतिशील विजन को अंजाम दिलाएगा।

फोरलेन सवेरा ढाबे के पास बस पलटी, जनहानि नहीं

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। मंहू-नीमच राजमार्ग पर सवेरा ढाबे के निकट एक यात्री बस पलट गई, जिसमें दो-तीन यात्रियों को चोट आई। हालांकि हादसे के समय बस में ज्यादा यात्री सवार नहीं थे। बताया जा रहा है कि बस सर्विसिंग कराने के बाद ट्रायल के लिए निकली थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हादसे में बस के क्लीनर को गंभीर चोट लगने की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक धाकड बस हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। बस को चालक और क्लीनर सर्विसिंग के बाद ट्रायल के लिए लेकर निकले थे। लेकिन, सवेरा ढाबे के निकट बस लहराने लगी और अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हादसे में बस के क्लीनर के पैर में गंभीर चोट लगने की खबर है। जिसे तत्काल बडे अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद हाईवे पर दलौदा और मंदसौर के बीच आने-जाने वाले वाहनों की कतार लग गई। खबर लगने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाकर बस को रास्ते से हटवाकर मार्ग को चालु करवाया।

विचार-मंथन

फिर लोस चुनाव के पहले किसान आंदोलन...

जब भी कोई आंदोलन किसी खास समय पर किया जाता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह आंदोलन इसी समय क्यों किया गया, यह आंदोलन तो पहले भी हो सकता था।किसी भी समय हो सकता था। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन को लेकर भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि यह आंदोलन तो पिछले साल किया जा सकता था,उससे पहले भी किया जा सकता था।सवाल उठना स्वाभाविक है कि किसान आंदोलन लोकसभा चुनाव के पहले क्यों किया जा रहा है। इसकी एक वजह तो यह है कि भाजपा पीएम मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव तीसरी बार जीतने जा रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मोदी को हराने के लिए इंडी एलायंस बनाया था। विपक्षी दल को उम्मीद थी कि यह गठबंधन हर सीट पर एक प्रत्याशी खड़ा कर भाजपा को हरा सकता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के भाजपा का साथ चले जाने के बाद गठबंधन के भविष्य पर ही सवाल पैदा हो गया है। रही सही कसर जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ जाकर पूरी कर दी है। सपा ने कांग्रेस को 11 सीट यूपी में देने की घोषणा कर दी है.ममता ने साफ कह दिया है कि वह कांग्रेस को बंगाल में कोई सीट नहीं देगी।टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। आप ने कह दिया है कि वह दिल्ली में कांग्रेस को एक सीट देगी। यानी कोई कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देना चाहता है तथा खुद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। सीधी सी बात है कि कांग्रेस उनका कहना माने या उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़ा करे। कांग्रेस कहना मानती है तो कमजोर होगी,नहीं मानती है तो उस पर आरोल लगेगा कि उसने अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किया। ऐसे में चुनाव भाजपा जीतती है तो कांग्रेस पर ही आरोप लगाया जाएगा कि उसी के कारण भाजपा जीती है। कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ उसे विपक्ष महत्व नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस न विपक्ष को संभाल पा रही है न ही अपने नेताओं को समझा पा रही है। ऐसे में जब इंडी गठबंधन से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रह गई है तो 13 फरवरी से शुरू हुआ किसान आंदोलन कांग्रेस व विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करेगा। राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि कांग्रेस किसानों के साथ है। यही नहीं राहुल गांधी ने तो लोकसभा चुनाव के लिए पहली गारंटी दे दी है कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कांग्रेस पूरी करेगी। जोश जोश में राहुल गांधी यह घोषणा तो कर दी है, हो सकता है कि कांग्रेस नेता सोच रहे हो कि अब तो राहुल गांधी किसानों के सबसे बडे नेता है। क्योंकि जिस मांग को पूरा करने का वादा पीएम मोदी ने नहीं कर सके हैं, उसे पूरा करने का वादा राहुल गाधी ने कर दिया है। इससे किसानों का वोट अब कांग्रेस को मिलेगा और वह पहले से ज्यादा सीटें जीत सकेगी। भाजपा को हरा नहीं सके तो किसान आंदोलन से भाजपा की सीटें भी कम होती है तो यह कांग्रेस केलिए बड़ी खुशी की बात होगी। यही कांग्रेस चाहती है और इसी के लिए कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ खडी है। किसानों की मांग पूरी करने का वादा कर रही है। भाजपा को नुकसान पहुंचाने का प्लान गठबंधन था,वह फ्लाप हो गया तो किसान आंदोलन कांग्रेस का प्लान बी है। किसान आंदोलन सफल होता है या नहीं इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा।

एमएसपी कानून का खर्च 10 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़

विजय विद्रोही

राहुल गांधी ने किसानों की एक बड़ी मांग सत्ता में आने पर पूरा करने का वादा कर के क्या तीर चला दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि उनका गठबंधन सत्ता में आया तो एम.एस.पी. को कानून बनाया जाएगा। मोदी ने सत्ता में आने पर स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू करने का वादा किया था, जिसमें किसानों को कुल लागत पर 50 फीसदी मुनाफा देने की बात कही गई थी लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे डाला कि वह इस सिफारिश को पूरा नहीं कर सकेगी क्योंकि ऐसा करने पर गेहूं, धान आदि का एम.एस.पी. 20 से 25 फीसदी बढ़ाना होगा और ऐसा होने पर बाजार में इन जिंसों के दाम इस कदर बढ़ जाएंगे कि महंगाई दर 20 फीसदी पार हो जाएगी। क्या राहुल गांधी का एम.एस.पी. को कानून बनाने का वादा भी महंगाई दर में इजाफा करेगा? कहा जा रहा है कि एम.एस.पी. को कानूनी जामा पहनाया गया तो भारत सरकार पर 10 लाख करोड़ का सालाना भार पड़ेगा। उधर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह भार 3 लाख करोड़ सालाना से ज्यादा नहीं होगा, जिसे सरकार वहन करने की क्षमता रखती है। तर्क दिया जा रहा है कि अगर सरकार कार्पोरेट घराने को 4 लाख करोड़ की सबसिडी और रियायतें दे सकती है तो अन्नदाता का भला क्यों नहीं कर सकती।

आप सवाल उठा सकते हैं कि आखिर यह 10 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? दरअसल भारत में हर साल एम.एस.पी. के तहत आने वाली 22 जिंसों का जितना भी उत्पादन होता है, उसका बाजार में मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें गेहूं , धान, मोटा अनाज, दलहन (उड़द, मूंग, चना, मसूर, मोठ, राजमा आदि) और तिलहन (मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी) शामिल हैं। वैसे इसमें अगर फल-सब्जियां और दूध-अंडे को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 40 लाख करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा का बैठता है। लेकिन फल-सब्जी की एम.एस.पी. पर सरकारी खरीद नहीं की जाती, लिहाजा उन्हें अलग रखा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि अगर एम.एस.पी. को कानून के दायरे में लाया गया तो भारत सरकार को किसानों से हर साल 10 लाख करोड़ रुपए की सरकारी खरीद करनी ही होगी। ऐसा हुआ तो आर्थिक कमर टूट जाएगी। कुछ लोग आधारभूत ढांचे के लिए रखे गए 11 लाख करोड़ के बजटीय प्रावधान से इसकी तुलना कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में 10 लाख करोड़ की सरकारी खरीद करनी होगी या 3 लाख करोड़ रुपए में ही सरकार का काम चल जाएगा। अगर 2020-21 को देखा जाए तो भारत सरकार ने गेहूं और धान की ही ढाई लाख करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की थी। स्वाभाविक है कि एम.एस.पी. को कानून बनाने या न बनाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, मिड डे मील, आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सरकार को ढाई लाख करोड़ रुपए का अनाज खरीदना ही पड़ता है। इसमें अगर दलहन और तिलहन की एम.एस.पी. पर सरकारी खरीद को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है। एक अनुमान के अनुसार किसान जितनी फसल उगाता है, उसका 25 फीसदी अपनी खपत के लिए अपने पास रखता है, यानि उसे बेचने के लिए न तो सरकार के पास जाता है और न ही मंडियों की शरण लेता है। दाल के मामले में तो किसान 40 फीसदी तक अपने पास घरेलू खपत के लिए रखता है। सरकारी खरीद के 3 लाख करोड़ और बाजार में नहीं आने वाले ढाई लाख करोड़ का हिसाब साढ़े 5 लाख करोड़ बैठता है। तो क्या भारत सरकार को 10 लाख करोड़ की जगह साढ़े 4 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार भुगतना होगा? नहीं। ऐसा भी नहीं है। आटा मिल मालिक, धान मिल मालिक, बिस्कुट आदि बनाने वाले गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, दाल खरीदते हैं। यह आंकड़ा डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लगभग बैठता है। तो इस तरह 7 लाख करोड़ रुपए का हिसाब आपके सामने है। फिर सरकार जो कृषि उत्पाद खरीदेगी, उसका एक हिस्सा अपने पास रखने के बाद बाकी का बाजार में बेचेगी भी। तो इस प्रकार से अगर एम.एस.पी. को कानून बनाया जाता है तो सरकार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का सालाना भार नहीं पड़ेगा। उल्टे इससे खेती छोड़कर शहर जा कर मजदूरी करने वाले फिर से खेतों से जुड़ सकेंगे। उन्हें लगेगा कि खेती करना मुनाफे का काम है, तो गांव छोड़ कर धक्के खाने शहर क्यों जाएंगे। कुछ जानकार तर्क देते हैं कि एम.एस.पी. को कानून बनाने के बाद सरकार ऐसी जिंसों पर एम.एस.पी. बढ़ाकर किसानों को उन जिंसों को उगाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिन्हें वह बदलते वक्त के साथ जरूरी समझती है। दाल के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हर साल मलेशिया से तेल मंगाने की जरूरत से बचा जा सकता है। तो क्या राहुल गांधी की गारंटी सचमुच महत्वपूर्ण है? देश में खेतिहर मजदूरों को जोड़ दिया जाए तो सीधे तौर पर खेती से करीब 20 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अगर एक घर में तीन वोटर भी हुए तो यह आंकड़ा 50 करोड़ पार जाता है। लेकिन किसान आंदोलन तो किसान के रूप में करता है लेकिन वोट देता है तो जाति में बंध जाता है। कुछ जानकारों का कहना है कि एम.एस.पी. को कानून बनाने की बजाय किसानों को तेलंगाना की रायतु बंधु योजना या ओडिशा की कालिया योजना जैसा लाभ दिया जाना चाहिए। इन योजनाओं में मोटे तौर पर किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपए की सबसिडी साल में दो बार (रबी और खरीफ) मिल जाती है। अगर औसत जमीन चार एकड़ है तो साल में 40 हजार रुपए की नकद सबसिडी। कुछ जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा का भावांतर योजना एम.एस.पी. का अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। इन योजनाओं में किसी जिंस के भाव तयशुदा भाव से कम होने पर सरकार उस नुकसान की भरपाई करती है।

रायबरेली से दूरी, सोनिया के लिए जरूरी या मजबूरी?

सिद्धार्थ शंकर गौतम

अतः उत्तरी भारत या कहें कि हिंदीभाषी राज्य राजस्थान का चुनाव कर उन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस को इस बहस से दूर करके भाजपा के एक मुख्य चुनावी मुद्दे की धार कुंद कर दी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सोनिया गांधी आखिर रायबरेली की अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट को छोड़कर क्यों चली गईं? उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभ सीटों में से एकमात्र यही सीट थी जो प्रदेश के कांग्रेसियों के लिए भाजपा के भगवे सूर्य के समक्ष दीये की भांति चमकती थी। तो क्या 2024 में राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा होने जा रहा है कि सोनिया गांधी को रायबरेली से भी अपनी हार नजर आ रही थी? एक निजी सर्वेक्षण संस्था द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया जिसमें यह तथ्य सामने आया था कि कांग्रेस के लिए रायबरेली में जीत की संभावना 45 फीसदी है। तो क्या इसी कारण सोनिया गांधी ने रायबरेली से पलायन का मार्ग चुना अथवा असल बात कुछ और है? सोनिया गांधी की राजनीतिक आमद ऐसे समय में हुई थी जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी न तो पार्टी को साध पा रहे थे और न ही गांधी-नेहरू परिवार के नाम की साख उनके काम आ रही थी। 1998 के उस दौर को कौन भूल सकता है जब सीताराम केसरी को उनके सामान के साथ कांग्रेस कार्यालय से निकाल दिया गया था और पार्टी की कमान सोनिया गांधी ने अपने हाथों में ले ली थी। इटली में जन्मी सोनिया गांधी को न तो देश की राजनीति की समझ थी और न ही इसकी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कोई मॉडल था किंतु अपने कुशल नेतृत्व के दम पर उन्होंने न केवल कांग्रेस को मजबूत किया वरन अटल-आडवाणी की भगवा आंधी के सामने डट कर खड़ी हो गईं। 2004 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री की स्वाभाविक उम्मीदवार थीं किंतु उनका विदेशी मूल का मुद्दा पद के आड़े आ गया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि एक दशक तक सत्ता-संगठन में उनकी पकड़ किसी से छुपी नहीं है। यहां तक कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी अपने दौरों में सोनिया गांधी से मिलने दस जनपथ आते थे। उस एक दशक में सोनिया गांधी ने जो चाहा वह किया। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस उस दशक में बेहतर स्थिति में थी और भाजपा दहाई की संख्या भी मुश्किल से पार कर पाती थी। अपना पहला

लोकसभा चुनाव उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीता था किंतु उत्तर प्रदेश की राजनीतिक महत्ता को समझते हुए उन्होंने बेल्लारी सीट छोड़ दी थी। वैसे भी रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, पीलीभीत जैसी सीटें गांधी-नेहरू परिवार के नाम से ही पहचानी जाती रही हैं और इन सीटों की जनता भी इस परिवार को वोटों का स्नेह देती रही है। यह लीक पिछली बार तब टूटी जब राहुल अमेठी से चुनाव हार गए।अब सोनिया गांधी का भी राजस्थान से राज्यसभा जाना रायबरेली के सामने यक्ष प्रश्न छोड़ गया है कि यदि सोनिया नहीं तो फिर कौन? सवाल यह भी है कि इन क्षेत्रों से पारिवारिक राजनीति का जो लगाव रहा, क्या वह समाप्त होगा? वैसे एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, वहां से सोनिया गांधी का जाना कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का एक और कारण बनेगा। राहुल गांधी अब संभवतः अमेठी का रुख नहीं करेंगे क्योंकि राम मंदिर लहर में उनके लिए वहां कुछ नहीं बचा है। वे लोकसभा में केरल की वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, ऐसी संभावना है। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, यह कांग्रेस का सबसे रहस्यमयी प्रश्न है और सोनिया गांधी रायबरेली से जीत ही जातीं, यह भविष्य के गर्भ में है। ऐसे में सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना कहीं न कहीं दोनों सदनों में गांधी-नेहरू परिवार की प्रासंगिकता बचाना अधिक लग रहा है।यदि लोकसभा में राहुल और राज्यसभा में सोनिया होंगी तो भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो पाएगा। फिर जिस प्रकार राज्य इकाइयों से पुराने कांग्रेसी हाथ का साथ छिड़ककर कमल दल की सवारी कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को पुनः रिवाईव करने में गांधी-नेहरू परिवार के नाम का सहारा चाहिए होगा और दोनों सदनों में परिवार का प्रतिनिधित्व इस काम को बखूबी अंजाम देगा।इसके अलावा सोनिया गांधी के राज्यसभा में होने से लोकसभा में राहुल को अधिक एक्सपोजर मिलेगा जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा तथा न्याय यात्रा के बाद राजनीतिक रूप से अधिक परिपक्व नजर आ रहे हैं।

तरक्की में कुछ आगे निकले सूबों की बढ़ती शिकायत

दक्षिणी राज्यों ने वित्तीय संघवाद पर फिर नाखुशी जताई है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना शिकायत कर रहे हैं कि उनकी वित्तीय आजादी छिन गई है, उनकी अपनी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की क्षमता सीमित हो गई है। अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से बेहतर दक्षिणी की ओर से विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में आया है, जब देश आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण के चार राज्यों में से कर्नाटक और केरल दिल्ली की सड़कों पर भी उतर आए। वे सभी इसे अपने अधिकार का मुद्दा, स्व-शासन का मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में इस कदम पर तीखा पलटवार किया है। उधर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का कहना है कि जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद के शासन की तुलना में राज्य के वित्त पर 20,000 करोड़ रुपये का सीधा असर पड़ा है। केरल के वित्त मंत्री का कहना है कि उनका राज्य 2023-24 में केंद्रीय हस्तांतरण और ऋण मंजूरी में 57,000 करोड़ रुपये से वंचित रह गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रणनीति के तहत एक नारा ही गढ़ दिया है, 'मेरा कर, मेरा हक' और पिछले सप्ताह उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए अपने मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली में डेरा डाल दिया था। सिद्धारमैया अतिरिक्त दबाव में हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय 50,000 करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की थी और अब पर्याप्त धन के अभाव में मुश्किल हो रही है। इस बीच, तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग को ज्ञापन सौंपकर राज्य को अधिक धन देने की मांग की है। समस्या की जड़ केंद्र और राज्यों द्वारा राजस्व संसाधनों को साझा करने के तरीके में निहित है। गौर करने की बात है कि केंद्र और राज्यों के बीच धन का हस्तांतरण केंद्र द्वारा हर पांच साल में गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2025 तक वैध हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का भी गठन कर दिया है, जो अगले पांच वर्षों के लिए अपनी सिफारिशें देगा। केंद्र और राज्यों द्वारा एकत्र प्रत्यक्ष और परोक्ष करों को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, एक साथ रख दिया जाता है और उसके बाद वितरण होता है। 14वें और 15वें वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व के रूप में क्रमशः 42 प्रतिशत और 41 प्रतिशत के हस्तांतरण की सिफारिश की थी। यह सिफारिश पिछले वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों से कहीं अधिक है और प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इसका जिक्र करते रहते हैं। दरअसल, सकल संग्रह अधिक है और राज्यों के साथ शुद्ध कर संग्रह ही साझा होता है, जो कम है। विगत पांच वर्ष को देखें, तो साल 2023-24 में केंद्र का सकल कर राजस्व 14.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 33.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 5.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें, तो राज्यों का हिस्सा दोगुना और केंद्र का हिस्सा दोगुने से अधिक हो गया है। इसके अलावा, केंद्र उपकर और अधिभार का अपना संग्रह राज्यों के साथ साझा नहीं करता है। केरल और तमिलनाडु को यह अतिरिक्त शिकायत भी है कि उनके बजट के बाहर के ऋण (राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण) को नेट उधार सीमा के तहत शामिल किया गया है, इससे इन राज्यों की ऋण लेने की क्षमता सीमित हो गई है। जहां दक्षिण के राज्यों को शिकायत है, वहीं उत्तर भारत के भाजपा शासित राज्य शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश में सामाजिक विकास सूचकांक कम है और आबादी अधिक है। चूंकि दक्षिणी राज्य इन सभी कारकों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए उन्हें वित्त आयोग की शर्तों की वजह से कम हिस्सा मिलता है।

सुडोकू पहेली क्रमांक- 5148

	5				4		6	
3				6	8	2		
4	6			9				1
					1		4	
	3	4		5		7	2	
	9		2					
6				8			7	9
		9	3	2				8
	7		9				5	

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक हैं, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी व खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

सुडोकू पहेली क्र. 5147

3	2	6	8	4	5	1	7	9
4	8	7	6	1	9	5	2	3
9	1	5	7	2	3	6	8	4
7	9	2	5	6	8	4	3	1
6	4	8	3	9	1	7	5	2
1	5	3	4	7	2	8	9	6
2	6	1	9	5	7	3	4	8
8	7	4	2	3	6	9	1	5
5	3	9	1	8	4	2	6	7

वर्ग पहेली 5148

संकेत: बाएं से दाएं
1. इस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने 12 अगस्त को जन्म लिया था (7)
6. दुर्भाग्य, दुर्दशा, संकट (3)
7. एक प्रकार का फल जो भगवान के भोग निमित्त चढ़ाया जाता है, कदली (2)
9. तिब्बत के बौद्धों के धर्माचार्य, घास खाने और पागुर करने वाला एक जंतु जो ऊंट जैसा होता है (2)
10. मुंशी, लिखने वाला, लेखक (3)
12. एक प्रकार का मंगल वाद्य, नफीरी (4)
13. एक सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त निकटवर्ती सभी मनुष्यों या वस्तुओं के लिए होता है (2)
14. इस देश को म्यांमार कहा जाता है (2)
15. राजा के लिए प्रयुक्त शब्द (3)
19. यह एक दिवंगत पूर्व मैं दस्यु रह चुकी थीं (5)
21. उथल-पुथल, भागदौड़, संचलन (4)
22. विधिवत, एक रिश्ता, मातामह (2)

ऊपर से नीचे
1. महाकाय, भीम, गजकाय (5)
2. तारतम्य, रूटीन, विन्यास, करीना (2)
3. स्वार्थ, खुदगर्जी, प्रयोजन (4)
4. भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री (5)
5. बरछा, भाला, नेजा, पाशनी (2)
8. अमादि करके कमाया हुआ धन (3)
9. उपस्थित करना, ले आना, लिवाना (2)
11. तिगुना, तीन बार उतना ही (3)
14. जंगली मेवा (4)
16. निर्मित होना, निर्माण होना, पनपना (3)
17. यह उत्तर भारत में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है इसका पौराणिक नाम यमुनी है (2)
18. एक प्रशंसासूचक शब्द (2)
20. प्रदान करना, प्रदान करना (2)

वर्ग पहेली 5147 का हल

खु	दी	रा	म	बो	स		रा
दि	म	न	हो	त		ज्यो	म
	क		र	वा	ना		ज
ला		ब	र	ल		ला	[illegible]
क	न्धा	दा	न		आ	द	त
ल	व			मा	ला		भा
	क	मा	ल		ली	ज	न
क	र्ण		भ	इ	रा		स

आज का राशिफल

मेष
वृषभ
मिथुन
कर्क
सिंह
कन्या
तुला
वृश्चिक
धनु
मकर
कुंभ
मीन

सीएम हेल्पलाइन पर न्याय की गुहार लगाती लाड़ली बहना

खेताखेड़ा, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व संचालित की गई लाडली बहना योजना में प्रदेश की एक करोड से अधिक महिलाओं को पात्रता के अनुसार लाभ दिया जा रहा मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2023 मैं लाडली बहनाओं को शुरुआत के तौर पर हर माह की 10 तारीख को ?1000 खाते में डालना शुरू किए गए बाद में राशि को बढाकर हर माह लाडली बहनों के खातो मे 1250 रुपये डाले जा रहे मध्य प्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली बहना योजना महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए संचालित की गई पात्रता के अनुसार प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं से फॉर्म भरे गए जिसके बाद महिलाओं को योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ।

जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में निवासरत सैकडो लाडली बहनाओं के खाते में राशि डलना बंद हो चुकी है लाडली बहना योजना में लाभ प्राप्त कर चुकी अधिकतर महिलाओं द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी एवं सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके शिकायत दर्ज भी कराई परंतु महिलाओं को संतुष्टिपूर्वक जवाब प्राप्त नहीं मिला जानकारी के अनुसार सीएम हेल्पलाइन 181 पर सैकडो प्रकरण लाडली बहनाओं के दर्ज किए गए लाडली बहना योजना में लाभ प्राप्त कर चुकी महिलाओं ने बताया कि शुरुआत के तौर पर पात्रता के अनुसार हर माह की 10 तारीख को हमारे खाते में पैसे डालते थे लेकिन अब पैसे खाते में नहीं डल रहे जिसकी शिकायत भी की गई संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आपके स्वयं के द्वारा लाडली बहना योजना का लाभ परित्याग किया गया लेकिन महिलाओं का मानना है उनके स्वयं के द्वारा लाभ परित्याग नहीं किया ना ही लिखित मे योजना से लाभ त्यागने संबंधित दस्तावेज नही दिया ऐसे में महिलाओं के बिना जानकारी के लाभ परित्याग हो रहा है लाडली बहना योजना से वंचित हुई महिलाओं ने बताया कि वह योजना की शर्तों कें अनुसार पात्र हैं उसके बावजूद भी सरकारी तंत्र की गलतियों की वजह से उन्हें अपात्र कर योजना से वंचित किया जा रहा है। जिससे महिलाओं के खाते में अब लाडली बहना योजना के पैसे डलना बंद हो चुके स्थानीय जिला प्रशासन को इस और ध्यान आकर्षित कर लाडली बहनाओं की समस्याओं का हल करना चाहिए।

क्या है लाभ परित्याग–पडताल मे जानकारी सामने आई की लाडली बहना योजना के अधिकारीक वेबसाइट पर लाभ परित्याग संबंधित एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जिसमें लाभ परित्याग संबंधित जानकारी भरना होती हैं योजना मे लाभ परित्याग वाले बटन को क्लिक करना होता है उसके बाद लाडली बहना योजना का क्रमांक समग्र आइडी और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होता है फिर उसके बाद लाडली बहना योजना मे रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है रिटर्न ओटीपी नंबर फार्मेट मे जमा करने के बाद फार्म सबमीट किया जाता है यह सब प्रोसेस पुरी करने के बाद महिलाओं को लाडली बहना योजना से आउट किया जाता है जिससे महिला को लाडली बहना योजना का लाभ मिलना बंद हो जाता है

भाजयुमो के शिविर में 35 यूनिट रक्तदान हुआ

पिपलियामंडी, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। भाजयुमो ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, पिपलिया मंडल अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने बताया शिविर में 35 युवाओं ने रक्तदान किय, इस दौरान जिला उपाध्यक्ष शिवराज सिंह घटावदा, जनपद सदस्य बंसीलाल, मंडल अध्यक्ष सामंत सिंह, युवा मोर्चा जिला महामंत्री चिंटू शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष राजू जाट, भेरूलाल, सांसद प्रतिनिधि दिलीप गोयल, विधायक प्रतिनिधि लोकेश कराडा, भाजपा नेता राजेश पटवा, मनोहर काबरा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेन्द्र भारद्वाज, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रिंकू गोतम, नप की पूर्व अध्यक्ष प्रवीणा गुप्ता सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, जन प्रतिनिधि सहित भाजपा और युवा मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सफाई कर्मचारियों की 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीएमओ को सौंपा

सात दिन में मांगे नहीं मानने पर करेंगे चरणबद्ध आंदोलन

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। सकल वाल्मीकि समाज संयुक्त मोर्चा संघ मन्दसौर ने 16 फरवरी को मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सुधीर कुमार सिंह को लम्बे समय से लंबित सफाई कर्मचारियों के 12 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की तथा मांगे नहीं मानने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी।

ज्ञापन में कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगे काफी समय से लंबित है। इस बाबत कई बार हमारे द्वारा मांगपत्र दिये जा चुके है। दिनांक 01.08.2023 को भी हमारे द्वारा मांग पत्र आपको दिया गया था। जिस पर आपके द्वारा पत्र दिनांक 3277/सीएमओ कक्ष/2023 दिनांक 23.08.2023 को हमारे प्रतिनिधि मण्डल को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया था। तत्समय आपकी उपस्थिति में मांगों पर चर्चा हुई तथा आपके द्वारा मौखिक रूप से मांगों का जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया था। तथा आपके द्वारा पत्र क्र. 3244/सीएमओ कक्ष/2023 दिनांक 22.08.2023 से भी उक्त मांगों का निराकरण करने संबंधी बात कही थी लेकिन अभी तक मांगों के संबंध में नगरपालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से सफाई कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। सफाई कर्मचारी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे है लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने से सफाई कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है। ज्ञापन में कहा कि उक्त मांगों का 7 दिवस में निराकरण किया जावे अन्यथा सफाई कर्मचारियों को चरणबद्ध आन्दोलन करने पर मजबूर होना पडेगा। जिसकी समस्त जवाबदारी नगरपालिका प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय सकल वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष राजाराम तंवर, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के संभाग अध्यक्ष प्रकाश तंवर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश चनाल, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शांतिलाल झांझोट, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीवन गोसर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष मनीष घारू, वीर मातादीन अम्बेडकर सेना के जिलाध्यक्ष थानसिंह घावरी, म.प्र. महावाल्मिकी पंचायत संभाग महामंत्री विक्रम तंवर, मंगल कोटियाना सतीश खेरालिया मनोहर फतरोड, संतोष गोसर अजय चनाल, आदि उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष पयामी ने दिए नपा वित्तीय बजट पर सुझाव

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। नगर पालिका इस साल का वित्तीय बजट वर्ष का प्रस्तावित है आने वाले साल के लिए जो बजट बनाया जाना है उसको लेकर मेरे द्वारा निम्न सुझाव दिए जा रहे हैं जो की बजट 2024 2025 में सम्मिलित किया जाए जिससे की प्राथमिकता के आधार पर वह कार्य हो सके और शहर वासियों को राहत मिल सके।

1. संपूर्ण मंदसौर शहर की नालियों की स्थिति जर्जर है उनका नए सिरे से निर्माण किया जाए टूटी हुई नालियों के कारण पानी मकान की नीव में भर रहा है जिससे शहर क्षेत्र के संपूर्ण मकान क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हो रहे हैं एवं नलों में भी क्षतिग्रस्त एवं टूटी नदियों के कारण गंदा पानी मिल रहा है जिससे नलों में गंदा पानी आने की शिकायत आए दिन शहर वासियों को रहती है। 2. संपूर्ण पुराने शहर में नालियों पर जालीकरण किया जाए जिससे की छोटी गलियों में आवागमन की समस्या सुलझाई जा सके। 3. मंदसौर शहर में जो पुराना शहर है जिसमें खानपुरा किला रोड जंनकुपुरा शुक्ला चौक गुदरी तोडा की छोटी गलियां है जहां पर कचरा वाहन नहीं पहुंच पाते हैं उन क्षेत्र के लिए छोटे कचरा वाहन की व्यवस्था करने की राशि इस बजट में रखी जाए। 4 पानी की नई टंकियां की व्यवस्था वनाने की इस बजट में की जाए ताकि मंदसौरवासी रोज पानी की सुविधा को प्राप्त कर सके। 5. हर वार्ड में नए बगीचा का निर्माण किया जाने का प्रावधान इस बजट में किया जाए। 6.प्रत्येक वार्ड में जिम उपकरण एवं महिला एवं एक पुरुष के लिए पृथक पृथक लगाया जाए 7. वार्ड में सार्वजनिक स्थान पर एवं धार्मिक स्थल पर सार्वजनिक बेंचेज रखने का प्रावधान भी इस बजट में किया जाए। 8. प्रत्येक वार्ड में झोनल के काम करवाने की राशि को बढाकर 10 लख रुपए तक किया जाए। 9. नगर पालिका के समस्त कर जैसे जलकर संपत्ति कर आदि जमा करने के लिए तत्काल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की जाए जिससे कि नगरपालिका को आमदनी में वृद्धि हो और लोगों को कोपरेशानियों का सामना न करना पडे।

शाप्रावि टिगरिया व चिकल्या में ऊनी स्वेटर वितरण हुए

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। महावीर पुस्तकालय एवं जीवनोपयोगी सामग्री नि:शुल्क वितरण समिति मंदसौर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को लगातार ऊनी स्वेटर नि:शुल्क वितरण किये जा रहे है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय चिकल्या गांव व टिगरिया बस्ती के विद्यालय में ऊनी स्वेटर वितरण किये गये।

इस अवसर पर नियमित विद्यालय आने वाले एवं अच्छी आदतों के बारे में बताया गया व बच्चों से मोबाइल व टीवी का उपयोग कम से कम करने की बात कही। रोज उठते-सोते समय भगवान की प्रार्थना करें। माता-पिता व गुरु का आदर करें। होमवर्क विद्यार्थी रोज करे व स्कूल समय पर आये। विद्यार्थियों को आदर्श बातें सिखाई गई। उपस्थित सभी विद्यार्थियों को राजकुमार सौलंकी, अशोक नलवाया, श्रद्धा श्रीवास्तव एवं श्रीमती निर्मला सुनार्थी ने नये स्वेटर पहनाये। चिकल्या गांव में विद्यार्थी को नये स्वेटर कपडे मांगीलाल गुर्जर, सीमापाल, राजकुमार सौलंकी, पायल एवं संस्था के सेवक अशोक नलवाया द्वारा पहनाये गये। शिक्षकों को बेग भेंट किये गये। सीमा पाल द्वारा अतिथियों का स्वागत किया एवं आभार व्यक्त किया। चिकल्या गांव व टिगरिया प्राथमिक विद्यालय में स्वेटर वितरण की तरह पूर्व समय में बोहराखेडी व अलावदा स्कूल में महावीर पुस्तकालय द्वारा स्वेटर वितरण किये गये। दोनों ग्रामीण क्षेत्र के पालकों एवं विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे पहनने के कपडे, कोर्स व प्रतियोगिता परीक्षा व सर्वधर्म की पुस्तकें घर ले जाकर नि:शुल्क लाभ उठावे। पालकगण, पुराने पहनने, ओढने व बिछाने के कपडे व्यर्थ न फेंके। साथ ही पुराने पुस्तके रद्दी में न बेचे एवं महावीर पुस्तकालय कोठारी नगर, संजीत नाका मंदसौर पर दान दे। डाइट कॉलेज के प्राचार्य श्री प्रमोद सेठिया के मार्गदर्शन में शिक्षक राजकुमार सौलंकी एवं अशोक नलवाया ने सराहनीय तन,मन, धन से सेवाएं दी।

पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के तहत मेगा फूड फेस्टिवल सम्पन्न

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर के प्राचार्य डा. उमा गगरानी ने जानकारी दी कि महाविद्यालय में संचालित ईको क्लब के अंतर्गत पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) पर्यावरण विभाग म.प्र.शासन भोपाल द्वारा प्रायोजित पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मेगा फुड फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत महाविद्यालय की 16 छात्राओं ने मिलेट्स के विभिन्न प्रकार के मीठे एवं नमकीन व्यजंन बनाये। इस फेस्टिवल की विशेष बात यह रही कि मिलेट्स (मोटे अनाज) से बने केक, कटलेट, चाट, खीर, सेव, लडडु, बर्फी, चिल्ले इत्यादि व्यंजन बनाये गये जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्णायक के रूप में डा.प्रेरणा मित्रा एवं सुश्री भारती सोनी उपस्थित थी। डा. मित्रा ने बताया कि मिलेट्स से बने इतने अधिक स्वादिष्ट व्यंजनों की उपलब्धता हो तो स्वाद के साथ शरीर भी स्वस्थ रहेगा। छात्राओं ने प्रत्येक व्यजंन के साथ व्यजंन में प्रयुक्त किये जाने वाले मिलेट्स के वानस्पतिक नाम के साथ ही व्यजंन की पोषण संबंधी विस्तृत जानकारी भी साझा की। उपरोक्त प्रतियोगिता में प्रथम स्थान साक्षी चन्द्रावत, द्वितीय स्थान पार्वती माली एवं तृतीय स्थान अनुष्का जैन एवं अनम बी ने प्राप्त किये। कार्यक्रम में महाविद्यालयीन स्टाफ के साथ महाविद्यालय की अन्य छात्राओं ने भी मेगा फुड फेस्टिवल में सहभागिता कर सफल बनाया।

जयपुर भेजी 30 क्विंटल लहसून को नडियाद मंडी में बेच दिया

पिकअप चालक व क्लिनर पर केस दर्ज

पिपलियामंडी, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। जयपुर भेजी लहसुन संबंधित फर्म पर नही पहुंची, व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने पिकअप ड्राइवर व क्लिनर के खिलाफ केस दर्ज किया। जानकारी के अनुसार पिपलिया कृषि मंडी में खान ट्रेडर्स फर्म के हाफिज अहमद ने पिपलिया पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि 14 फरवरी को उन्होंने पिकअप (आरजे 52 जीबी 1090) से 30 क्विंटल लहसुन सांई ट्रेडर्स जयपुर के ज्ञानचन्द्र एण्ड संस पर भेजी थी। लेकिन जयपुर सांई ट्रेडर्स के संचालक अशोकभाई ने बताया कि उन्हें लहसुन नही मिली। जब पिकअप ड्राइवर कालूसिंह के मोबाइल पर कॉल किया तो मोबाइल बंद था, उसके साथी सुरेश मीणा से बात की तो सुरेश ने बताया हमने लहसुन नडियाद मण्डी में बेच दी है। व्यापारी की शिकायत पर पिपलियामंडी पुलिसने आरोपी पिकअप चालक व क्लिनर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

कविता लेखन के माध्यम से बाल हिंसा के प्रति लोगों को कर रही है जागरूक

मनासा, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई मनासा की स्वयंसेविका और आगाज इंटर्न माया गुर्जर बाल हिंसा को समाप्त करने हेतु विभिन्न गतिविधियां एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं उसी कडी में माया कविता के माध्यम से भी लोगों को बाल हिंसा के प्रति जागरुक कर रही है।।

कितना सुन्दर कितना प्यारा
कितना निश्छल है ये बचपन
लाड दुलार प्रेम का सागर
फूलों का उपवन है बचपन
डांट डपट बिन मतलब के ही
कोमल हृदय पर अंगार सी क्यों बौछार करे
लडाई झगडा हिंसा तुम करते
मन: स्थिति पर इनके प्रभाव पडे
पढाई लिखाई है जरुरी मगर
क्यों लादते जैसे बाल मन को बोझ लगे
चारों तरफ होगा गर हिंसा फिर
मन मस्तिष्क पर कैसे शुद्ध विचार चढे
उम्र है जो मृग मस्त खुशियों की सौगात सी शोषण से हो ग्रस्त
फिर कैसे बाल मन स्वयं का विकास करें।

कल आर्य समाज मंदसौर में होंगे आयोजन

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। आर्य समाज के अध्यक्ष श्री मधुसूदन आर्य ने बताया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का 200वां जन्मशताब्दी वर्ष पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आर्य समाज मंदसौर द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2024, रविवार को स्वामीजी का जन्मदिवस मनाया जायेगा। जिसके तहत रविवार को प्रात: 9 से 10 बजे तक यज्ञ एवं यज्ञ के पश्चात स्वामी दयानन्द सरस्वती के भजन होंगे तत्पश्चात् स्वामीजी के जीवन पर आर्य समाज के विद्वानों द्वारा प्रकाश डाला जाएगा। श्री आर्य ने आर्य समाज के समस्त सदस्य एवं अन्य नागरिकगणों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर दिए सख्त निर्देश

नीमच, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्य म से खाद्य पदार्थों मैं मिलावट को लेकर प्रदेश के समस्तश संभागायुक्तु एवं जिला कलेक्टेरों के साथ समीक्षा बैठक की। श्रीमती राणा ने भारत सरकार एवं राज्य सर्विलांस प्लान अनुसार खाद्य पदार्थों कीं नियमित रूप से जांच करने और उसके आधार पर मिलावटी क्षेत्रों का चिन्हांकन कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। श्रीमती राणा ने कहा, कि जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा, नापतौल, दुग्ध संघ एवं पुलिस आदि विभागों से सम्मिलित विशेष निगरानी दलों का गठन कर खाद्य पदार्थों मैं गुणवत्ता की निगरानी की जाए। जिलों में स्थित दुग्ध केंद्र, चिलिंग प्लांट एवं कलेक्शन सेंटर पर चलित प्रयोग शालाओं के माध्यम से दूध तथा दूध से बने हुये विभिन्न खाद्य पदार्थों मैं गुणवत्ता की निगरानी के लिए इनके सेम्पल की नियमित जांच करायें। उन्होंने जिलों में जनसंख्या के अनुपात में लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक में खाद्य, गृह एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समाधान आपके द्वार योजनांतर्गत 24 को लोक अदालत एवं शिविर का आयोजन

नीमच, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुमोदन अनुसार समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत 24 फरवरी, 2024 को संपूर्ण मध्यप्रदेश में लोक अदालत एवं शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग, वन विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

राजस्व, पुलिस, वन, नगरपालिका, नगरपरिषद् एवं विद्युत विभाग से संबंधित विवादों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होता है जिनमें कई प्रकरण समझौता योग्य होते है, अत: ऐसा विचार किया गया, कि यदि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाए जिससे

कि ऐसे प्रकरणों को वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम जैसे मध्यस्थता, लोक अदालत एवं सुलह के द्वारा उनके अंकुरण के स्तर पर ही निराकृत किया जा सके इससे न केवल सारभूत रूप से न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों में लंबित प्रकरणों में कटौती होगी बल्कि बडी संख्या में जनमानस को मुकदमे बाजी की अवांछित कठिनाई से भी बचाया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विजय कुमार सोनकर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि प्रारंभिक स्तर पर ही मुकदमों को पक्षकारों के मध्य सौहाद्र पूर्ण तरीके से समाप्त किए जाने के उद्देश्य से समाधान आपके द्वार योजना की परिकल्पना की गई एवं इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर समझौती योग्य प्रकरणों को जैसे की न्यायपालिका, राजस्व, पुलिस, वन, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं विद्युत विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनका निराकरण करना है। इसी उद्देश्य से शुक्रवार को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सुशांत हुद्दार ने हरी झंडी दिखाकर समाधान आपके द्वार योजना के प्रचार रथ को रवाना किया। प्रचार रथ द्वारा सम्पूर्ण जिले में भ्रमण कर योजना का प्रचार प्रसार किया जावेगा, ताकि अधिक से अधिक प्रकरण समाधान आपके द्वारा योजना अंतर्गत निराकृत हो सके और आमजन इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सके।

डोडाचूरा को एनडीपीएस एक्ट से मुक्त किए जाने की मांग

प्रधानमंत्री को एडवोकेट रत्नावत ने जनहित में लिखा पत्र

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। एडवोकेट गौरव रत्नावत ने जनहित में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर मांग की कि डोडाचूरा को एनडीपीएस एक्ट से मुक्त किया जाए।

एडवोकेट श्री रत्नावत ने चिट्ठी में उल्लेख किया कि 'अमृतकाल में एवं ग्राम चलो अभियान' के तहत् प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और मधयप्रदेश शासन आपसे अनुरोध है कि भ्रष्टचार से मुक्ति के लिये डोडाचुरा को एनडीपीएस एक्ट से मुक्त किया जाए। एक आम नागरिक होते हुए अपील करता हूँ कि, डोडाचूरा (अफीम काश्त के वेस्ट पदार्थ पापीस्ट्रॉ) को गम्भीर से गम्भीर अपराध एनडीपीएस एक्ट से बाहर किया जाना अति आवश्यक है। वर्ष 1985 से पूर्व 6 माह के कारावास की सजा का प्रकरण होता था, उसके बाद में कॉंग्रेस सरकार के समय वित्त मंत्रालय ने आम भारत के कृषकों एवं विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित नहीं किये व (अमेरिका) गैर भारतीय के बहकावे में आकर डोडाचुरा को एनडीपीएस एक्ट में सम्मिलित करते हुए सजा का प्रावधान गम्भीर कर दिया, जबकि डोडाचुरा मात्र अफीम का वेस्ट पदार्थ है, पापीस्ट्रॉ में कोई मार्फीन नहीं होती है, एवं म.प्र.शासन की लेबोरेटरी द्वारा भी कभी-भी डोडाचुरा में मार्फीन का प्रतिशत नहीं बताती है, जबकि एनडीपीएस एक्ट के अपराध में 0.2 प्रतिशत मार्फीन होना आवश्यक माना गया, है। उसी प्रकार गैर भारतीयों ने अपने उपयोग में लिये जाने वाले भाग को एनडीपीएस एक्ट से बाहर रखा है, एवं उक्त डोडाचुरा से शासकीय अधिकारी अवैध रूप से भ्रष्टचार करते हैं, ओर कई बार उक्त अफीम पट्टेजो शासन के द्वारा दिये जाते है, उनको बचाने के लिये भी किसान लोग अवैध राशि अधिकारियों को अदा करते हैं, जिससे उनका लायसेंस रद्द नहीं हों, ओर भ्रष्टचार को रोकने के लिये अखबारों में भी कई बार पढने को मिलता है कि, किसान द्वारा फर्जी प्रकरण में फसाये जाने की घोंस देने से उसने आत्महत्या कर ली है, व राजनेतिक हस्तक्षेप से अवैध राशि अधिकारियों से वापस भी दिलवाई गई है।

एडवोकेट श्री रत्नावत ने पत्र में उल्लेख किया कि वेस्ट प्रदार्थ को एनडीपीएस एक्ट से बाहर किया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में भी किसानों के साथ भ्रष्टचार बढता जावेगा एवं आत्महत्याऐं बढेंगी। यही विनम्र अपील है कि, तत्काल रूप से डोडाचूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर किया जाना न्यायहित में परम् आवश्यक है।

गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना के सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करें-जैन

कलेक्टर ने की गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना एवं ग्रीनको प्रोजेक्टर की समीक्षा

नीमच, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना एवं ग्रीनको पावर जनरेशन प्लांट के सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करवाएं जाए। निर्माण कार्यो में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखे। यह निर्देश कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने शुक्रवार को 1400 करोड के गांधी सागर जल प्रदाय योजना के तहत हर घर नल से जल योजना के निर्माण कार्यो और 1440 मेगावाट के हाईड्रो पावर जनरेशन प्लांट के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, जल निगम के महाप्रबंधक श्री जितेन्द्र सिह राणावत, श्री सुनील सिह तोमर, मोहम्मद हसीन खान एवं ग्रीनको के प्रबंधक श्री अमित सोनी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जल जीवन मिशन के

महाप्रबंधक श्री जितेन्द्र राणावत ने बताया, कि इस योजना के तहत नीमच जिले के 646 गांवों में नल से शुद्ध जल प्रदाय किया जाकर, 1.97 लाख परिवारों को लाभांवित किया जावेगा। नीमच जिले में लगभग 415 कि.मी.पाईप लाईन बिछाने का कार्य हो गया है। शेष कार्य तेजी से जारी है, योजना के तहत एक इंटेकवेल 168.72 एम.एल.डी.क्षमता का निर्माणाधीन है। साथ ही बस्सीकला में 136 एम.एल.डी.क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी 20 हेक्टेणयर क्षेत्र में बन रहा है। बीस नग क्लीयर वाटर सम्पवेल एवं पम्प हाउस एवं कुल 318 आरसीसी ओव्हरहेड टैंक में से 129 नग आर.सी.सी.ओव्हर हेड्टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही 4 हजार कि.मी. से अधिक की पाईपलाईन एवं 1620 कि.मी.क्लीयर वाटर पाईपलाईन बिछाने का कार्य भी पूर्ण हो गया है। शेष कार्य तेजी से चल रहा है। सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण कर लिये जायेंगे। बैठक में ग्रीनको के अधिकारियों ने बताया नीमच जिले के गांधी सागर जलाशय से सटे खिमला ब्लॉक में लगभग 13 हजार करोड लागत से ग्रीनको पॉवर जनरेशन प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से जारी है। इस परियोजना के तहत गांधी सागर का जल एक बडे सम्पोवेल में स्टोरेज कर उससे बिजली उत्पादित की जावेगी। इस प्रोजेक्ट की विशेषता यह है, कि इसमें पानी का पुर्न:उपयोग हो सकेगा और बिजली उत्पादन से पानी व्य र्थ नहीं बहेगा। इस प्रोजेक्ट का कार्य मार्च 2025 तक पूरा कर बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो जायेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पाईप लाईन बिछाने से क्षतिग्रस्त सडकों के रेस्ट्रोरेशन का कार्य गुणवत्तापूर्ण तेजी से किया जाए, जिससे कि ग्रामीणों को कोई असुविधा ना हो।

मंदसौर मंडी भाव

उपज	आवक बोरी में	न्यूनतम	अधिकतम
मक्का	43	2196	2461
उडद	2	4401	5701
सोयाबीन	2948	3550	4629
गैहु	2214	2370	3256
चना	110	4800	5751
मसुर	350	4800	5840
धनिया	1070	4240	5950
लहसुन	23000	5101	18551
मैथी	272	4751	5981
अलसी	484	4500	5060
सरसो	3500	4001	4556
तारामीरा	2	4556	4556
इसबगोल	2	9300	15351
प्याज	546	610	1201
कलोंजी	24	15600	17741
डॉलर	1	5090	5090
तिल्ली	4	14470	14571
मटरसुखी	2	3300	3400
असालीया	377	5500	6890

मप्र कांग्रेस की राजनीति में थम नहीं रही गुटबाजी, अकेले पड़े कमल नाथ

भोपाल, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस में गुटबाजी थम नहीं रही है। सबसे ताकतवर माने जाने वाले कमल नाथ पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के कारण ग्वालियर- चंबल में आई रिक्तता को भरने के लिए कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्य सभा का टिकट देकर कद बढ़ाया है लेकिन प्रत्याशी चयन के मुद्दे पर मची खींचतान ने गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया है।

राज्य सभा चुनाव में राहुल गांधी और कमल नाथ के बीच की खटास भी जगजाहिर हो गई। हालांकि, अशोक सिंह को राज्य सभा भेजने के पीछे भी कमल नाथ की रणनीति ही सफल रही। जहां ओबीसी राजनीति के नाम पर कमल नाथ, राहुल गांधी की पसंद की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को रोकने में सफल रहे, वहीं अशोक सिंह का नाम बढ़ाकर अरुण यादव और जीतू पटवारी को भी रोक लिया। ये दोनों ही ओबीसी हैं। राहुल गांधी की नाराजगी के बाद हाल ही में कमल नाथ को हटाकर पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था।

राहुल से बढ़ रही खटास...

दरअसल, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद से कमल नाथ का मन मध्य प्रदेश में नहीं लग रहा है। इसकी शुरूआत तब हुई, जब कांग्रेस हाइकमान ने कमल नाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी और उन्हें नेता प्रतिपक्ष न बनाकर आदिवासी नेता उमंग सिंघार को यह पद सौंप दिया गया। यहीं से राहुल गांधी और नाथ के बीच खटास पैदा हुई थी। इसलिए वे मप्र की राजनीति में सक्रिय न रहकर खुद दिल्ली लौटना चाहते हैं। साथ ही वे यह भी नहीं चाहते कि बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ को किसी तरह से प्रभावित किया जाए। इसलिए वे अपने अन्य विकल्पों पर भी समानांतर रूप से प्रयास कर रहे हैं।

कांग्रेस में भी अलग-थलग पड़े नाथ...

कांग्रेस में भी इन दिनों कमल नाथ अलग-थलग पड गए हैं। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तब नाथ का नाम भी अध्यक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाया गया था, उनकी और सोनिया गांधी की दो दौर की मुलाकात भी हुई थी। तब नाथ ने यह सोचकर अपने कदम पीछे खींच लिए थे कि वे मप्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना लेंगे तो पार्टी में ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। लेकिन परिणाम कुछ और हुआ, कांग्रेस जीती बाजी हार गई।

नाथ के नजदीकी सूत्र तो यह भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता दिल्ली में रहकर उनके खिलाफ विष उगल रहे हैं और सुनियोजित ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान कई विषयों को लेकर सुरजेवाला और कमल नाथ के बीच असहमति रही। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत भी हुई थी और कमल नाथ और दिग्विजय सिंह से दिल्ली बुलाकर बात की गई थी।

पुत्र प्रेम में बढ़ रही गुटबाजी

दरअसल, कांग्रेस को नजदीक से देखने वाले राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चाहे कमल नाथ हों, या दिग्विजय सिंह, दोनों के पुत्र प्रेम के कारण मप्र कांग्रेस में गुटबाजी बढ रही है। दोनों नहीं चाहते कि मप्र में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार या अरुण यादव जैसे युवाओं के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो। यदि ऐसा हुआ तो नकुल नाथ और जयवर्धन सिंह का सियासी भविष्य संकट में पड जाएगा। इसी कारण दोनों दिग्गज इन युवा नेताओं को रोकने के अवसर पर एक हो जाते हैं।

कांग्रेस के ही लोग बताते हैं कि मीनाक्षी नटराजन के नाम का विरोध होने पर पार्टी नेतृत्व ओबीसी वर्ग से अरुण यादव को राज्यसभा भेजना चाहता था। लेकिन, दोनों ने ऐसी चाल चली कि ग्वालियर-चंबल में सिंधिया का प्रभाव कम करने के लिए ओबीसी के अशोक सिंह के नाम पर सहमति बना ली गई।

हाशिए पर अजय सिंह...

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह भी इसी गुटबाजी के कारण हाशिए पर पडे हैं। पार्टी में उनकी पूछपरख करने वाला भी कोई नहीं है। दो-दो बार मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह को बढाने के बजाए नाथ-दिग्गी की जोडी उनके विरोधी कमलेश्वर पटेल को आगे बढाकर राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बना दिया था।

सीमेंट से भरे लोडिंग वाहन में सवारी, पलटने से 16 घायल, ओवरलोडिंग के चलते लगातार हो रहे हादसे

रतलाम, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चालक वाहनों में ओवर लोड करने से बाज नहीं आ रहे है। परिवहन विभाग व पुलिस की यदा-कदा होने वाली कार्रवाई भी इस पर रोक नहीं लगा पाई है। एक सप्ताह पहले सैलाना के बोदिना रोड पर चलती जीप की छत से गिरने पर किशोरी की मौत हो गई थी। वहीं गुरुवार शाम करीब सवा चार बजे रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम देवला के समीप यात्रियों से भरा लोडिंग वाहन पलट गया। इससे उसमें सवार 16 व्यक्ति घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार छोटे लोडिंग वाहन में ग्राम सिंगत से सीमेंट भरकर वाहन चालक रावटी जा रहा था। उसने वाहन में 20 से अधिक लोगों को भी बैठा लिया था। ग्राम देवला के समीप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे वाहन में सवार 11 वर्षीय सविता पुत्री बालू डामोर निवासी ग्राम बोरवा, 12 वर्षीय धापू पुत्री केहरिंग निवासी ग्राम जामपाडा, 14 वर्षीय राधि पुत्री केहरिंग निवासी ग्राम जामपाडा, 29 वर्षीय लीलाबाई पत्नी बहादुर मईडा, छह वर्षीय आशीष पुत्र बहादुर मईड, 30 वर्षीय जमुना पत्नी दिनेश, सात वर्षीय राजेश पुत्र बालू चरपोटा, 60 वर्षीय रामी पत्नी कोदर चरपोटा, 55 वर्षीय रुपली पत्नी वरसिंह भाभर, 27 वर्षीय श्यामूसिंह मईडा पुत्र दुल्हेसिंह मईडा, 50 वर्षीय बसंती पत्नी रामसिंह सिंगाड सभी निवासी ग्राम मेघलाखाली आदि घायल हो गए। घायलों को रावटी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सविता व दिनेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया।

मात्र दो दिन चली कार्रवाई–एक सप्ताह पहले बोदिना के पास चलती जीप की छत से गिरने से 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई थी। इस पर जिला परिवहन विभाग व पुलिस ने संयुक्त रूप से सैलाना व आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर कुछ वाहन चालकों के खिलाफ क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर चालानी कार्रवाई की थी। दो दिन चले चेकिंग अभियान के बाद कार्रवाई बंद कर दी गई। आटो में 15 से 20 व मैजिक वाहनों पर 35 से 40 यात्री तक बैठाए जा रहे हैं। वहीं जीप में 30 से 35 लोगों को बैठाया जा रहा है। लोगों का कहना है चेकिंग अभियान निरंतर चलाया जाना चाहिए। ओवरलोडिंग पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा तो किसी भी दिन बडा हादसा हो सकता है।

फांसी के फंदे पर झूला युवक, मौत

मनासा, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। नगर के जूना साथ कॉर्नर क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक 38 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मनासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतार कर पंचनामा बनाया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए मनासा के सरकारी अस्पताल भेजा गया। जहां परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया।जानकारी के अनुसार बडा तालाब के समीप रहने वाले विशाल पिता गोपाल नाथ योगी ने अज्ञात करणों के चलते अपने जुना साथ स्थित मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक विशाल ने तब फांसी लगाई जब सभी परिजन बडा तालाब स्थित मकान पर थे। मृतक सिलाई का काम करता था। वह अपनी पत्नी, दो बच्चों और परिवार वालों के साथ रहता था। फिलहाल मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। आशा-उषा-आशा सहयोगी एकता यूनियन म.प्र. (सीटू) के राष्ट्रव्यापी आव्हान के तहत प्रदेश सहित मंदसौर जिले की समस्त आशा-उषा कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षकों सहित योजना कर्मी ने 16 फरवरी को एक दिवसीय हडताल की। इस दौरान स्थानीय गांधी चौराहा पर विशाल धरना प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार एवं सीएमएचओ को ज्ञापन भी दिया गया। गांधी चौराहा पर धरने को संबोधित करते हुवे आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों के चलते महंगाई लगातार बढ रही है लेकिन आशा एवं पर्यवेक्षकों को जीने लायक वेतन दिये जाने एवं भविष्य निधि, ईएसआई, ग्रेच्युटी सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने की मांगों को सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को, सरकारी अधिकारियों की देखरेख एवं मार्गदर्शन में आशा उषा पर्यवेक्षक वर्षों से सेवाएं दे रही है। इसके बावजूद आश एवं पर्यवेक्षकों को कर्मचारी के रूप में नियमित करने की मांग को नजर अंदाज कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा पांच साल से हमारे वेतन में वृद्धि नही की है। जिसके चलते केंद्रीय ट्रेड युनियनों एवं स्कीम वर्कर्स की अखिल भारतीय हडताल के आव्हान पर आशा-उषा-आशा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश (सीटू) ने भी इस हडताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। जिला अध्यक्ष माधुरी सौलंकी ने हमारी मांगों को तत्काल पुरा किया जाये।

शिविर में मतदाता जागरूकता दिवस मनाया

पिपलियामंडी, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। शासकीय महाविद्यालय पिपलिया की ओर से गांव मुन्देडी में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिवर में चतुर्थ दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया। श्रमदान हेतु ग्राम भ्रमण किया। जल की स्वच्छता और जल के तल की स्वच्छता का संदेश देते हुए ग्रामीण जल की टंकी पर श्रमदान किया। थीम के अनुरुप मतदाता जगरूकता हेतु गांव में रैली निकाली, बौद्धिक में विधि महाविद्यालय मंदसौर के प्रो. सुनील कुमार बढोडिया ने संविधान मतदान का अधिकार किस किस को देता है और कितनी उम्र वाले नागरिक को देता है जानकारी दी।अभाविप के पूर्व विभाग सहसंयोजक पवन शर्मा ने मतदान को दान क्यों कहा जाता है उसका अर्थ समझाया। भारत निर्वाचन आयोग राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर नितिन शर्मा ने ईवीएम की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि वह कैसे काम करती है ।अध्यापक समरथ पाटीदार पक रामायण काल से मतदान के महत्व को बताया साथ ही व्यक्ति विकास के पहलू पर सत्य को परिभाषित किया और कहा की निर्भीक होकर सत्य के साथ जीना चाहिए। मावि प्रधानाध्यापक श्रीमती देवकन्या चोहान, डॉ. केएल लोहार, डॉ अरुण नरगावे, प्रो सचिन कारपेंटर, नारायण पालीवाल सहित स्वयं सेवक उपस्थित रहे। संचालन महिमा पाटीदार ने किया। आभार प्रो पूजा जाटवा ने माना।

राजस्व व पशु पालन विभाग की भूमि का व्यय कर नवीन सम्पत्ति का निर्माण किया जाएगा

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में सुशासन भवन सभा कक्ष में पुनर घनत्व करण योजना के अंतर्गत बैठक आयोजित की गई। नाहटा चौराहा स्थित राजस्व की 0.575 है. भूमि तथा पशु पालन विभाग की 0.314 है. भुमि को व्ययन प्रस्तावित किया गया। इसके व्ययन से प्राप्त होने वाली राशि से शासकीय नवीन सम्पत्ति का निर्माण किया जाएगा। यह दोनों भूमि शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित है, तथा इन पर निर्मित सम्पत्ति पुरानी हो कर जीर्ण हो चुकी है। योजना का प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन म. प्र. गृह निर्माण मण्डल के द्वारा तैयार कर बैठक में रखा गया। जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत म. प्र. गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से साधिकार समिति को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

केंद्रीय श्रम संगठन हड़ताल एवं ग्रामीण बंद के समर्थन में मंदसौर एम आर यूनियन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। केंद्रीय श्रम संगठनों एवं संयुक्त किसान मोर्चे के आव्हान पर 16 फरवरी को ओद्योगिक हडताल और ग्राम बन्द के आव्हान पर मंदसौर दवा प्रतिनिधि यूनियन सदस्यो द्वारा नारेबाजी कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन दवा बाजार में किया गया।

मंदसौर एम आर यूनियन अध्यक्ष दिनेश चंदवानी ने बताया की फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर केन्द्रिय श्रम संगठनों की हडताल और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ग्रामीण बन्द को समर्थन देते हुए भारत के सभी दवा प्रतिनिधियों को दो घन्टे काम बन्द रख सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, जिसमे मंदसौर दवा प्रतिनिधियो द्वारा भी जोर-शोर से नारेबाजी कर सांकेतिक धरना दवा बाजार मे दिया।हमारी प्रमुख मांगो मे दवाओं पर जीरो प्रतिशत जीएसटी, 26000/- न्यूनतम वेतन, 10000/- मासिक पेंशन, अस्पतालों में काम करने का अधिकार, एसपीई ऐक्ट 1976 का पालन करना इत्यादि शामिल है। मंदसौर यूनियन सचिव मयंक चुनेकर ने कहा की न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत प्रत्येक पांच वर्षों में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2014 के बाद से ही न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण नहीं किया गया। इस अवसर पर सह सचिव उपेन्द्र राय, महेश धनोतिया, मयंक राणा, अनिल शर्मा, संदीप जैन, हेमंत चंदेल, लोकेश कुमावत, अनिल प्रजापत, पलाश सोनी, कौशल आर्य, भरत पाटिदार, प्रफ्फूल पाटिदार, कैलाश चौहान, अमित कुमार, अजय कुमावत, अरुण जाट, तालिब मंसुरी, पियूष कुमार, मनीष महिया, मनीष साल्वी इत्यादि उपस्तिथ थे।

दौबड़ा के पंचायत सचिव निलंबित

पिपलियामंडी, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। जिला पंचायत सीईओ ने एक आदेश में मल्हारगढ तहसील की ग्राम पंचायत दौबडा के सचिव नरेन्द्रसिंह चोहान को निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार मल्हारगढ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मंदसौर जिला पंचायत की समीक्षा बैठक में बताया कि दोबडा के सचिव नरेन्द्रसिंह चौहान अक्सर ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रहते है, उनसे संपर्क करने पर हमेशा मोबाइल बंद रहता है। ग्राम पंचायत में आंगनवाडी भवन निर्माण, मनरेगा के निर्माण कार्य, नाला निर्माण आदि निर्माण कार्य 500 दिवस से अधिक लंबित है, एम हेल्प लाइन बंद करवाने हेतु बार-बार निर्देशित करने पर भी कोई रुचि नहीं ली जा रही है, सचिव पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मल्हारगढ की अनुशंसा पर जिला पंचायत सीईओ ने सचिव चौहान को निलंबित कर दिया।

प्रोजेक्ट उन्नति प्रशिक्षण का हुआ समापन

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। म.प्र. डे- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रोजेक्ट उन्नति के हितग्राहियों का 10 दिवसीस पशुपालन, डेयरी एवं वर्मी कम्पास्ट प्रशिक्षण प्रदया किया गया। जिसमें हितग्राहियों को विभाग के अधिकारियों द्वारा जैविक खेती, पशुपालन एवं शासकीय योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण में आरसेटी डायरेक्टर एवं पशुपालन विभाग अधिकारी उपस्थित थे।

सहज सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे हरि ओम बरसोलिया

अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्धारा श्रद्धा सुमन समर्पित

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सदस्य हंसमुख मिलनसार कवि हृदय श्री हरिओम बरसोलिया का मंदसौर से दिल्ली की यात्रा के बीच दुखद निधन हो गया। 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन आपका निधन हुआ तथा 15 फरवरी को पशुपतिनाथ महादेव के पास स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि के अवसर पर साहित्य परिषद के सदस्यों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि समर्पित की। 16 फरवरी को खानपुरा में चारभुजा नाथ मंदिर पर आयोजित उठावने में भी उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित किये।

इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भावसार सचिव नंद किशोर राठौड, अजय डांगी, चंदा डांगी, नरेंद्र कुमार त्रिवेदी, राजेंद्र तिवारी, विजय अग्निहोत्री, गोपाल बैरागी, संजय भारती, प्रदीप शर्मा और धुरव जैन की उपस्थिति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने उनके साथ गुजारे क्षणों को याद किया तथा अपने संस्मरण सुनाए। श्री बरसोलिया साहित्य परिषद द्वारा आयोजित कवि गोष्ठियों में उत्साह पूर्वक भाग लेते थे तथा अपने निवास स्थान पर भी कार्यक्रम आयोजित करते थे। वे एक सरल हृदय कवि थे। साहित्य परिषद द्वारा उनकी रचनाओं को संकलित कर उन्हें प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा। उनकी स्मृति सदैव अक्षुण रहेगी और वे सभी को हमेशा याद आते रहेंगे।

समाधान आपके द्वार शिविर का आयोजन 21 को

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार चल रहे समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के तत्वाधान में 21 फरवरी 2024 को संजय गांधी उद्यान मंदसौर शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, क्षेत्रीय परिवहन विभाग के सहयोग से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी, लर्निंग लाइसेंस आदि बनवाए जाने अथवा संशोधन किया जाएगा। जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री हर्ष सिंह बहरावत ने बताया की समाधान आपके द्वार योजना का आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजस्व, पुलिस, वन, नगर निकाय, विद्युत विभागों के एवं न्यायालय में लंबित शमनीय मामले तथा अन्य प्रिलिटिगेशन मामलों का त्वरित एवं सुलभ निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया की उपरोक्त विभागों से संबंधित किसी भी समस्या हेतु संबंधित विभाग से योजना अंतर्गत संपर्क कर सकते है, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के कार्यालय में आवेदन कर सकते है। शिविर में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने दस्तावेज बनवाएं अथवा संशोधन करवा सकते है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण 19 से

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 की तैयारियों के मद्देनजर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के उपजिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह 19 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश के 362 अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण देंगे। लोकसभा निर्वाचन के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में विधिक जानकारी दी जाएगी। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में होगा और प्रत्येक चरण में 3-3 बैच होंगे। प्रशिक्षण सुबह 9.30 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा।

रेल्वे अंडरब्रीज के नीचे सालभर पानी भरे रहने से हादसे को लेकर प्रस्तुत जनहित याचिका में सुनवाई हुई

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। लोकपयोगी अदालत मंदसौर मे रेल्वे स्टेशन अंडर ब्रीज, गीता भवन अंडर ब्रीज को लेकर विनोद सालवी, महेश कुमार मोदी, महेश समंदर अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत जनहीत याचिका मे शुक्रवार को रेल्वे स्टेशन प्रबंधक मंदसौर, मुख्य न.पा. अधिकारी मंदसौर को जवाब प्रस्तुत करना था। जिस पर न.पा. के इंजिनियर उपस्थित होकर न्यायालय में बताया कि अंडर ब्रीज के पास नाले का सीमांकन कर पानी रिसाव को रोकने का प्रयास कर अगली तारिख तक न्यायालय को अवगत करायेगें। वही रेल्वे स्टेशन प्रबंधक की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया गया। जिस पर आगामी पेशी लोक उपयोगी न्यायालय द्वारा आगामी पेशी 02 मार्च 2024 रेल्वे प्रबंधक द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर आगामी कार्यवाही कि जावेगी। ज्ञात है कि रेल्वे अंडरब्रीज एवं गीता भवन अंडरब्रीज - के नीचे साल भर पानी भरा रहने से 2 पहिया वाहन चालकों पहिये फिसलकर आये दिन गिरकर हादसे हो रहे हैं। लेकिन रेल्वे विभाग एवं न.पा. विभाग द्वास इस और ध्याने आर्कषण नही दिया जा रहा है।

** नाम परिवर्तन **

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अनीता पिता रामस्वरुप दर्ज है एवं समस्त शैक्षणिक रिकार्ड, अंकसूचियों में मेरा नाम अनीता दर्ज है।

वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया, दलौदा शाखा में मेरा नाम अनीता व्यास दर्ज हैं, जिसे मैं अनीता के रूप में परिवर्तित करना चाहती हूं। अतः सूचित किया जाता है अनीता व्यास और अनीता एक ही है।

महिला को पीटा, दो पर प्रकरण दर्ज

पिपलियामंडी, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। मारपीट के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। आमली भाट (जावद) निवासी पूजा बावरी ने मल्हारगढ थाने पर शिकायत दर्ज कराई मैं अपने पीहर लसुडिया कदमाला आई थी, यहां चंदवासा निवासी चचेरे भाई पंकज पिता गोवर्धनलाल बावरी व उसका दोस्त विष्णु पिता बगदीराम बावरी मिले, विष्णु बोला कि तेरे पति को छोड मुझसे शादी कर ले। मैंने विरोध किया तो दोनों ने मारपीट की। बीच-बचाव करने आए मेरे पति के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 19 को

मंदसौर, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। नोडल अधिकारी प्रशिक्षण द्वारा बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू रूप से संपादन के लिये नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए। नियुक्त अधिकारी का प्रशिक्षण 19 फरवरी को टी.एल बैठक के पश्?चात सुशासन भवन कार्यालय सभागृह में आयोजित किया जाएगा।

सट्टा अंक लिखते पकड़ा

पिपलियामंडी, 16 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। पुलिस ने सट्टा अंक लिखते आरोपी को पकडा। मुखबिर की सूचना पर मल्हारगढ पुलिस ने सट्टा अंक लिखते अकील मेवाती को पकडा। आरोपी से सट्टा उपकरण व नकदी जब्त की।

श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला दलौदा

तहसील दलौदा जिला मंदसौर म.प्र.

विज्ञप्ति

दिनांक- 15.02.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला तहसील दलौदा जिला मंदसौर द्वारा निर्माणधीन दुकानों का आधिपत्य लिखित शर्तों के अनुसार दिये जाने हेतु दिनांक 03.03.2024 को दोपहर 3.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, दुकाने अभी निर्माणाधीन है जो आगामी 04 माह में पूर्ण रूप से निर्मित होकर आधिपत्य प्रदान किया जावेगा। प्राप्त आवेदन पत्रो का लाट मौके पर दिनांक 04.03.2024 को समय प्रातः 11 बजे से दुकान क्र. B-1 से B-7 तक का लाट निकालकर आधिपत्य प्रदान करने हेतु सुनिश्चित किया जावेगा। लाट निरन्तर दुकान क्र. B-1 से लगायत B-7 किया जायेगा।

निर्माणधीन दुकानों का विवरण

दुकानों का विवरण	दुकान की साईज	वार्षिक भुगतान किराया प्रत्येक दुकान का	आधिपत्य प्रदाय करने हेतु प्रत्येक दुकान की राशी
दलौदा चौपाटी में दलौदा सीतामऊ रोड पर B-1 से B-7	25 फीट X 11 फीट ल. चौ. 275 वर्ग फीट	12000/ बारह हजार रुपये प्रति दुकान (1000 / मासिक किराया)	30,00,000/- रुपये तीस लाख

शर्तें प्रत्येक दुकान का आधिपत्य सत्य हेतु। हेतु निर्धारित आवेदन पत्र । श्री अखिलानन्द सरस्वती ग्रामीण गौशाला दलौदा कार्यालय (नवीन गोशाला क्र. 2) पर प्रति दुकान हेतु राशी रुपये 2100/- (दो हजार एक सौ) शुल्क जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। शुल्क की जमा राशी वापसी योग्य नहीं होगी।

निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2024 से 02.03.2024 तक समय प्रातः 11.00 से दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगे।

आवेदन पत्र प्रति दुकान हेतु राशी रुपये 10,00,000/- दस लाख रुपये नगद या बैंक ड्राफ्ट जो कि श्री अखिलानंद ग्रामीण गौशाला के नाम देय होगा। (चेक मान्य नही होगा) राशी के साथ दिनांक 15.02.2024 से 02.03.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे समय समाप्त पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त राशी अमानत स्वरूप है तथा लाट में दुकान आवंटित नही होने पर चेक द्वारा राशी वापस भुगतान कर दी जावेगी। दुकान आवंटन होने पर अमानत राशी समायोजन पश्चात प्रति दुकान शेष राशी रुपये 20,00,000/- बीस लाख रुपये व वार्षिक भाड़ा 12,000/- बारह हजार रुपये कुल राशी 20, 12,000/- बीस लाख बारह हजार रुपये 3 माह में जमा कर अनुबंध निष्पादित कर आधिपत्य प्राप्त किया जा सकेगा। समय पर राशी प्राप्त नहीं होने की दशा में आपका आवंटन निरस्त करने का अधिकार श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला को रहेगा। आवंटित दुकानों क का उपयोग अधिपत्यधारी द्वारा स्व व्यावसाय हेतु किया जावेगा। तथा जो विधि अनुसार व शासन द्वारा प्रतिबंधित व्यावसाय के उपयोग के लिए नहीं किया जा सकेगा।

विशेष - यह दुकाने संस्था द्वारा बनाई गई है, यह संस्था जीव दया, पशु पक्षियों का संरक्षण करती है तथा दुकानों के पास धार्मिक स्थान होने से इन दुकानों पर मांस, मदिरा, अण्डा आदि घृणास्पद व्यवसाय पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन अध्यक्ष श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला दलौदा की अनुमति बगैर नहीं किया जावेगा।

दुकान मात्र व्यावसयिक उपयोग हेतु है, दुकान की भूमि व उपर की छत का आधिपत्य श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला दलौदा का रहेगा। दुकानों की मरम्मत आदि कार्य अधिपत्यधारी (किरायदार) को स्वयं के व्यय से संस्था की अनुमती लेकर कराना होगा।

दुकान का किराया प्रत्येक 3 माह में माह अप्रेल, जुलाई अक्टोम्बर एवं जनवरी की 5 तारीख तक अग्रिम जमा कराना होगा। दुकान के किराये का प्रति 3 वर्ष में पुनःरीक्षण कर 10 प्रतिशत कर बढ़ाने का अधिकार श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला दलौदा के पास रहेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर आधिपत्य वापस लेने का अधिकार श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला दलौदा को रहेगा।

अन्य किसी प्रकार के विषय में श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला दलौदा का निर्णय अंतिम होगा। अन्य जानकारी समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक गौशाला कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की सकती है।

महेन्द्र कुमार जैन सचिव
श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गोशाला दलौदा
मो. 9575939045

आशाराम पाटीदार अध्यक्ष
श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गोशाला दलौदा
मो. 9753368373

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक आशुतोष नवाल के लिए गुरु मीडिया एण्ड इंटरटेनमेन्ट कम्पनी, शक्ति नगर मन्दसौर से मुद्रित एवं 77 लक्ष्मीनगर, वेदान्त विहार मन्दसौर से प्रकाशित। (हर प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र मन्दसौर रहेगा) संपादक– आशुतोष नवाल RNI-MPHIN2006/20356
समाचार पत्र में छपे विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र उत्तरादायी नहीं है एवं विज्ञापनो में प्रकाशित विचार विज्ञापनदाता की निजी राय है। इससे समाचार पत्र का कोई संबंध नहीं है। फोन 495831, मो. 9425105927,28 ashugurumds@gmail.com, ashu_guru2@yahoo.co.in